CLASS -12

सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था

बजट का अभिप्राय - लोक कल्याणकारी राज्यों में मे सरकार को जिम्मेदारी होती है कि सामाजिक, आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को लागू करना । सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सार्वजनिक व्यय करती है तथा सार्वजनिक व्यय के लिए वित्त का प्रबंधन करती है। वित्तीय साधनो को जुटाना एवं विवेक पूर्वक व्यय करना अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है इसलिए वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व ही वित्तीय वर्ष के अनुमानित व्यय एवं प्राप्तियों का एक विवरण तैयार किया जाता है जिसे बजट के नाम से जाना जाता है।

बजट की प्रमुख परिभषाएं

बिभिन्न विद्वानों ने बजट को बिभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है कुछ मुख्य परिभषाएं निम्नवत हैं -

टेलर के अनुसार " बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है यह आगामी आय के अनुमान तथा बजट वर्ष के प्रस्तावित व्ययो के अनुमान साथ साथ प्रदान करता है "।

रेने स्टोर्न " बजट एक ऐसा प्रपत्र जिसमें सार्वजनिक व्यय की एक स्वीकृत योजना होती है " ।

फ़िंडले शिराज के अनुसार " संक्षेप में बजट मे गतवर्ष की आय एवं व्यय का विवरण आने वाले वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय के अनुमान तथा घाटों को पूरा करने हेतु साधनों के मार्ग या बचत को वितरित के प्रस्ताव सम्मिलित होते है " ।

उपरोक्त परिभषाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बजट आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार कि अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय का मदवार विवरण होता है ।

बजट के उद्देश्य

बजट सरकार कि उन विकास नीतियों एवं उद्देश्यों का सूचक होता है जिन्हे सरकार बजट के माध्यम से हासिल करना चाहती है ।

1. **आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना** बजट का उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को तेज करना होता है ताकि लोंगो का जीवन स्तर उन्नत किया जा सके। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार करों में रियायत देकर उत्पादन क्रियाओं को प्रोत्साहित कर सकती है । सरकार सार्वजनिक व्यय कर आधारभूत साधनो सड़क, नहरें, बिजली आदि का निर्माण कर सकती है सरकारी उपक्रमो की स्थापना की जा सकती है ।

2. **निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर करना** सरकार रोजगार की नई योजनाओं का निर्माण करके तथा गरीबों को अधिक से अधिक सामाजिक लाभ देकर निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर कर सकती है ।

3. **आय में असमानता दूर करना** आय की असमानता दूर करने के लिए सरकार कर एवं व्यय नीति का प्रयोग कर सकती है। अमीरों की आय एवं उनकी उपभोग वस्तुओं में अधिक कर लगाकर तथा गरीबो को आर्थिक सहायता, शिक्षा तथा स्वास्थ आदि सेवाएं निशुल्क प्रदान कर उनका जीवन स्तर उठाया जा सकता है ।

पदम सिंह फर्सवाण, प्रवक्ता अर्थशास्त्र

4. **संतुलित क्षेत्रीय विकास** सरकार संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु पिछड़े क्षेत्रों के लिए बिशेष नई सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना कर सकती है । तथा निजी क्षेत्र को कर में छूट देकर उत्पादन हेतु प्रोत्साहित कर सकती है ।

5. **आर्थिक स्थिरता** अर्थब्यवस्था में आर्थिक तेजी एवं मन्दी से नियंत्रण किया जा सकता है। सरकार तेजी के समय बचत का बजट तथा मन्दी के समय घाटे का बजट बनाकर आर्थिक स्थिरता प्राप्त करती है ।

बजट के संघटक संरचना

6. बजट के संघटक एवं संरचना से अभिप्राय बजट के विभिन्न अंगो से है बजट के दो घटक होते है।

(अ) बजट प्राप्तियां

(ब) बजट व्यय

(अ) बजट प्राप्तियां बजट प्राप्तियों से आशय एवं वित्तीय वर्ष मे सरकार को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली मौद्रिक प्राप्तिओं (आय) से है । इसे सार्वजनिक आय भी कहते है। बजट प्राप्तिओं को दो भागो मे वर्गीकृत किया जा सकता है।

(1) **राजस्व प्राप्तियां** (i) राजस्व प्राप्तियां वे सरकारी प्राप्तियां जिन से (i) सरकार कि कोई देनदारी उत्पन्न नहीं होती है । (ii) सरकार की परसम्पत्ति मे कोई कमी नहीं होती है राजस्व प्राप्तियां कहलाती है जैसे करों तथा गैर करों से प्राप्त आय राजस्व प्राप्तियां है।

(2) **पूंजीगत प्राप्तियां** - वे सरकारी प्राप्तियां जिनके -(i) सरकार की देनदारी उत्पन्न होती है या (ii) जिनसे सरकार की परिसम्पत्तियों में कमी होती है पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। पूंजीगत प्राप्तियों के तीन प्रकार की प्राप्तियां (ऋणों की वसूली, आतंरिक एवं विदेशी ऋण तथा विनिवेश) सम्मिलित होती है।

बजट व्यय

सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विभिन्न मदों पर किये जाने वाला व्यय को बजट व्यय कहा जाता है। इसे सार्वजनिक व्यय के नाम से जाना जाता है। सरकारी व्यय का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण के साथ आर्थिक विकास को गति देना होता है ।

(1) **राजस्व व्यय** जिस व्यय से (i) सरकारी परिसम्पतियों का निर्माण नहीं होता है और (ii) सरकार की देनदारी कम नहीं होती है, राजस्व व्यय कहलाते है । जैसे वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, कर्मचारियों का वेतन आदि इसके उदाहरण है ।

(2) **पूंजीगत व्यय** जिस व्यय से (i) सरकार को परिसम्पतियों का निर्माण होता है या सरकार की देनदारी कम होती है पूंजीगत व्यय कहलाता है । सरकार द्वारा घरेलू या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयर खरीदना, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों एवं राज्य निगमों को ऋण देना, मशीन एवं उपकरणों पर व्यय आदि इसके उदाहरण है ।

सार्वजनिक व्यय के अन्य प्रकार

(अ) विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय

विकासात्मक व्यय उन क्रियाओ पर किया जाने वाला व्यय जो प्रत्यक्ष रूप में देश के आर्थिक, सामाजिक विकास से सम्बन्धित होते है । विकासात्मक व्यय कहलाता है । उदाहरण के लिए कृषि, औधोगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ, सामाजिक कल्याण, आदि पर किया जाने वाला व्यय।

गैर विकासात्मक व्यय सरकार की आवश्यक सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय गैर विकासात्मक व्यय कहलाता है । ये व्यय गैर विकासात्मक क्रियाओं से सम्बंधित होता है। उदाहरण के लिए रक्षा, प्रशासन, पर किया जाने वाला व्यय आदि। यद्यपि गैर विकासात्मक व्यय आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से सहायक नहीं होता है लेकिन आर्थिक विकास के चक्र (पहिया) में तेल की तरह कार्य करके उसे कार्यशील बनाये रखता है।

योजनागत व्यय तथा गैर योजनागत व्यय

योजनागत व्यय भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था है यहाँ पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पंचवर्षीय योजना से सम्बंधित विकासात्मक कार्यक्रमों पर किया जाने वाला सरकारी योजनागत व्यय कहलाता है। कृषि ,ऊर्जा, संचार, उद्योग, यातायात आदि पर किया गया व्यय योजनागत व्यय में सम्मिलित होते है ।

गैर योजनागत व्यय पंचवर्षीय योजनाओ से सम्बंधित व्ययों के अतिरिक्त सभी सरकारी व्यय गैर योजनागत व्यय कहलाते है। उदाहरण के लिए भूकंप पीड़ितों को आनाज एवं गृह निर्माण के लिए दी गई राहत गैर योजनागत व्यय कहलाता है।

बजट के प्रकार

सामान्यतः सरकारी बजट के दो प्रकार होते है।

(अ) संतुलित बजट (ब) असंतुलित बजट

संतुलित बजट संतुलित बजट वह बजट है जिसमें बजट प्राप्तियां एवं बजट व्यय दोनों बराबर होते है। अर्थात
संतुलित बजट = बजट प्राप्तियां = बजट व्यय

परम्परावादी अर्थशास्त्री संतुलित बजट के पक्षधर थे। 1930 की महामंदी के पश्चात् आर्थिक विचारको का मत था कि देश में बेरोजगारी तथा आर्थिक समस्यों का प्रभावपूर्ण ढंग से हल में संतुलित बजट सहायक नहीं होता है।

<u>असंतुलित बजट</u> असंतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित बजट प्राप्तियां एवं अनुमानित व्यय बजट व्यय बराबर नहीं होते है अर्थात
असंतुलित बजट = बजट प्राप्तियां ≠ बजट व्यय

असंतुलित बजट के दो प्रकार होते है।

(i) **<u>बचत का बजट या अंतिरेक बजट</u>**

बचत का बजट उस बजट को कहते है जिसमे सरकार की अनुमानित बजट प्राप्तियां सरकार की अनुमानित बजट व्यय से अधिक होती है

बचत का बजट = सरकार की अनुमानित बजट प्राप्तियां > सरकार की अनुमानित बजट व्यय

प्रायः मुद्रा स्फीति की दशा में बचत का बजट उपुक्त माना जाता है क्योकि बचत का बजट अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग को घटाकर स्फीतिक अंतराल को कम करने में सहायक होता है।

(i) घाटे का बजट - घाटे का बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित बजट प्राप्तियां अनुमानित बजट ब्यय से कम होती है ।

घाटे का बजट =बजट व्यय >बजट प्राप्तियां

घाटे के बजट से अर्थव्यवस्था में विस्तारवादी शक्तियां बलवती होती जाती हैं। घाटे का बजट मंदी में उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालकर अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में सहायक होती है।

<u>बजटीय घाटे</u>

बजट घाटे का अभिप्राय उस स्थिति से है जहाँ सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है ।अर्थात कुल व्यय और कुल आय के अंतर को बजट घाटा कहा जाता है ।

बजटीय घाटा = कुल व्यय - कुल आय

= (राजस्व व्यय = पूंजीगत व्यय) - (राजस्व प्राप्तियां + पूंजीगत प्राप्तियां)

<u>बजटीय घाटे के प्रकार एवं माप</u>

प्रायः सरकार के वार्षिक घाटे में तीन प्रकार के घाटे सम्मिलित होते है ।

1 **<u>राजस्व घाटा</u>** - राजस्व घाटे से अभिप्राय सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर आय + गैर कर आय) की तुलना में राजस्व व्यय के अधिक होने से है । संक्षेप में राजस्व घाटा राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों में अधिकता है ।

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियां

2 **<u>राजकोषीय घाटा</u>** - राजकोषीय घाटा एक विस्तृत अवधारणा है। राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार के कुल व्यय (राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय) का उधार छोड़कर कुल पूंजीगत प्राप्तियां (राजस्व प्राप्तियाँ + उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां) पर अधिकता है ।

राजकोषीय घाटा =
बजट व्यय (राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय) - (राजस्व प्राप्तियाँ + उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां)

राजकोषीय घाटे का अधिक होना इस बात का प्रतीक है कि सरकार को अधिक धन उधार लेना होगा।

<u>प्राथमिक घाटा</u> राजकोषीय घाटे तथा भुगतान किये जाने वाले ब्याज का अंतर को प्राथमिक घाटा कहलाता है । दूसरे शब्दों में प्राथमिक घाटे राजकोषीय घाटे में ब्याज के भुगतान को घटाकर ज्ञात किया जाता है ।

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

प्राथमिक घाटा यह स्पष्ट करता है कि देश की सरकार को कितने ऋण कि आवश्यकता है सरकार को ब्याज के भुगतान के अलावा अपने और खर्च चलाने के लिए कितने ऋण कि आवश्यकता है।

<u>कर</u>

कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है जिसके बदले में सरकार से प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है ।

<u>करों के प्रकार</u>

<u>प्रत्यक्ष कर</u> - प्रत्यक्ष कर यह कर है जिसे जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही कर का भुगतान अपनी आय से करता है । इस कर को टाला नहीं जा सकता है और न ही इसका भार अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जा सकता है । जैसे आय कर जिस व्यक्ति कि आय पर लगाया जाता है उसका भर उस व्यक्ति को स्वयं उठाना पड़ता है। आयकर उपहार कर सम्पत्तिकर आदि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है।

<u>अप्रत्यक्ष कर</u> - अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति इसका भुगतान अपनी आय से नहीं करता है बल्कि उसका भुगतान किसी अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। अर्थात कराघात तथा करपात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क, व्यापार कर सेवाकर आदि इसके उदाहरण है ।

<u>प्रत्यक्ष कर</u>	**<u>अप्रत्यक्ष कर</u>**
प्रत्यक्ष कर का भार उस व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है जिस पर लगाया जाता है ।	अप्रत्यक्ष कर का भार हस्तांतरित किया है सकता है। जैसे लगाए जाते है उत्पादक पर लेकिन भुगतान उपभोक्ता करता है ।

ये कर आय एवं सम्पति पर लगाया जाता है ।	ये कर वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाए जाते है ।
इन करों का भर अमीरों पर अधिक तथा गरीबों पर कम पड़ता है क्योंकि ये प्रगतिशील होते है ।	इन करों का भार गरीबों एवं अमीरों पर सामान रूप से पड़ता है क्योंकि ये अनुपातिक होते है ।
इन करों से बचा नहीं जा सकता है ये अनिवार्य होते है ।	इन करों से बचा जा सकता है यदि हम वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग न करे ।
उदाहरण - आयकर, सम्पत्तिकर, निगमकर, उपहार कर।	उदाहरण - व्यापार कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सड़क कर, मनोरंजन कर, सेवा कर

<u>राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर</u>

<u>राजस्व प्राप्तियाँ</u>	**<u>पूंजीगत प्राप्तियाँ</u>**
ये प्राप्तियाँ सरकार की देनदारी उत्पन्न नहीं करती है ।	ये प्राप्तियाँ सरकारी देनदारी उत्पन्न करती है।
इन प्राप्तियाँ के कारण सरकार की परिसम्पतियों में कमी नहीं होती है ।	इन प्राप्तियाँ के कारण सरकार की परिसम्पतियों में कमी आती है ।
इन प्राप्तियाँ में कर तथा गैर कर आय सम्मलित होती है ।	इन प्राप्तियाँ में ऋण कि वसूली, उधार तथा विनिवेश सम्मलित होते है ।
इनकी प्रकृति नियमित होती है ।	इनकी प्रकृति अनियमित होती है।